ट्रैफिक पुलिस हुई नाकाम, जाम से 'राहत' दिलायेगी एफएमडीए, सैकड़ों करोड़ के टेंडर छोड़ने की तैयारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पूरे शहर की तमाम चौड़ी-चौड़ी सड़कें अवैध कब्जों एवं वाहन पार्किंग के चलते इतनी संकरी होकर रह गई है कि हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। एक डीसीपी व दो एसीपी तथा सैंकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों व होमगार्डों की तैनाती के बावजूद शहर को जाम से मुक्ति दिलाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है।

जाम से मुक्ति के लिये अब एफएमडीए (फ़रीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण) सैंकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर सामने आई है। पहले चरण में नीलम चौक से बाटा चौक तथा बाटा चौक से केसी रोड को जाम मुक्त करने की योजना है। इस योजना के पहले भाग में नीलम व बीके चौक के गोल चक्करों को छोटा किया जायेगा तथा दोनों के बीच में पेट्रोल पम्प के लगभग सामने बनाये गये यू-टर्न-कट को भी समाप्त किया जायेगा। इस कट को इसलिये बनाया गया था कि वाहनों को पेट्रोल पम्प की ओर जाने के लिये बीके चौक का चक्कर न लगाना पड़े। इस कट के बनने से बीके चौक को जाम से काफी राहत मिली हुई है जिसे अब बंद करने की तैयारी है।

इसी सड़क पर नेहरू ग्राऊंड की ओर जो नाला है उसे भी स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। विदित है कि यह नाला हार्डवेयर चौक से बीके चौक तक आने वाली सड़क के साथ-साथ पचासों साल से चला आ रहा है। बीके चौक से नीलम चौक होते हुए रेलवे लाइन तक जा रहा है और वहां से एनआईटी रेलवे स्टेशन होते हुए आगे निकल रहा है। आखिर अब एफएमडीए इस नाले को उठा कर कहां ले जायेगा? ले जाना कहीं नहीं है इसके नाम पर जनता के धन को बर्बाद जरूर किया जायेगा।

इसी चरण के तीसरे भाग में सैंकड़ों करोड़ की लागत से बने नीलम पुल से एलिवेटेड सड़क द्वारा बीके चौक को जोड़ा जायेगा। इसके साथ-साथ बीके से केसी की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करके उसके नीचे अंडरपास बनाने की भी योजना है। बीके से हार्डवेयर चौक की ओर जाने वाली सड़क पर भी फुट ओवरब्रिज, जिस पर चढ़ कर लोग सड़क पार करेंगे, बनाने की योजना है। अब कोई पूछे इन मूर्खों से भला कौन पुल की सीढ़ियां चढ़ कर सड़क पार करेगा? जहां तक बात है अंडरपास की तो शहर में पहले से ही बने अंडरपास की हालत शहरवासी बखूबी देख रहे हैं।

गौरतलब है कि शहर का निर्माण करने वालों ने 75 साल पहले सड़कों के लिये 200-300 फीट तक जगह छोड़ी थी, परन्तु शासक वर्ग की जन विरोधी नीतियों और लालच के चलते जानबूझकर सड़कों को संकरा बना दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र की तमाम सड़कें आज भी दोगुणी चौड़ा होने की क्षमता रखती है। जरूरत है तो केवल राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छाशक्ति की। बीके से नीलम तक की सड़क पर बने फुटपाथ पर रेहड़ियों के कब्जे करा दिये गये हैं। पैदल व साइकिल पर चलने वालों को भी मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है। इसके अलावा इन दोनों चौकों पर हर समय, शाम को अंधेरा होने के बाद खासतौर पर ऑटो-रिक्शा वालों का कब्ज़ा इस कदर हो जाता है कि वाहनों का वहां से निकल पाना दूभर हो जाता है। एक-दो नम्बर चौक की स्थिति तो सबसे बद्तर हो जाती है।

बीके केसी रोड पर केएलमेहता कॉलेज के सामने लालबत्ती तो लगा दी गई लेकिन वहां पर सड़क की जो व्यवस्था होनी चाहिये थी उसकी ओर किसी ने ध्यान

नहीं दिया। लालबत्ती लगाते समय बाईं ओर मुड़ने वाले ट्रैपिक के लिये सदैव स्लिप रोड बनाई जाती है जो कि यहां पर नहीं है। इसके चलते केसी की ओर से आने वाले जिन वाहनों को पांच नम्बर के भीतर जाना होता है वे भी लालबत्ती पर फंसे रहते हैं। इसी तरह पांच नम्बर के भीतर से आने वाले जिन वाहनों को बीके की ओर जाना होता है वे भी फंसे रहते हैं। इतना ही नहीं इस टी प्वाइन्ट पर पांच नम्बर में जाने वाली सड़क बहुत ही खतरनाक अवस्था में है।

शहर भर की बदहाल सड़कों की मामूली मरम्मत करने फुटपाथ एवं साइकिल ट्रैक बनाने तथा बने हुए फुटपाथों को कब्जों से मुक्त कराने की अपेक्षा शासक वर्ग का पूरा ध्यान सैंकड़ों करोड़ के टेंडर जारी करके लूट कमाई की ओर है। लगता है कि मौजूदा सड़कों की हालत संवारने की बजाय सरकार एलिवेटेड सड़कों के प्रोजेक्ट बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी श्रंखला में बल्लबगढ़ के अम्बेदकर चौक से मोहना को जाने वाली सड़क पर से अवैध कब्जे एवं पार्किंग हटाने की बजाय एलिवेटेड रोड बनाने की चर्चा चलाई जा रही है।

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

भ्रष्टाचार रोकने का जुनून या ई-पोर्टल द्वारा रिश्वत बढ़ाने पर लगा है जोर

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पिछले दिनों गृहमंत्री डॉ. अमितशाह अपने कमजोरी लाल खट्टर को जो ताकत का इंजेक्शन लगा कर गये थे उसका असर दिखने लगा है। बेशक यह ताकत उनके दफ्तर अथवा सदन के चारदीवारी के भीतर ही प्रदर्षित हो रही हो, पर हो तो रही है। ई-टेंडरिंग के विरुद्ध संघर्षरत सरपंचों को कड़ाई से जवाब देते हुए वे फर्माते हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार रोकने का जुनून है जिसके लिये ई-टेंडरिंग एवं डिजिटलाईजेशन जरूरी है। भ्रष्टाचार रोकने के लिये इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के बीच में वे किसी जन प्रतिनिधि एवं नेता की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर अपना अटल विश्वास जताने वाले खट्टर क्या इतने नासमझ हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि इस नई व्यवस्था ने सरकारी दफ्तरों में पहले से ही व्याप्त भ्रष्टाचार को कितने गुणा बढ़ा दिया है? न केवल बढ़ा दिया है आम जनता की पूरी ऐसी-तैसी कर रखी है। न तो पोर्टल चलते हैं न बाबू काम करते हैं और न ही अफ़सर काम करना चाहते हैं। काम केवल तभी होते हैं जब काम की मोटी 'फीस' मिल जाये। डिजिटलाईजेशन के ठेके केवल उन संघी ठेकेदारों को कमाई करने के लिये दिये जाते हैं जिन्हें न तो काम का पता होता है और न ही काम के तरीके का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जयपुर की याशी कम्पनी का है जो आईडी बनाने के नाम पर लोगों की आईडी बिगाड़ने के बदले 57 करोड़ लेकर चलती बनी।

जरूरतमंद लोग जो बाबू के आमने-सामने बैठकर सीधे-सीधे ले-दे कर अपना काम निकाल लेते थे, वे अब साइबर ठगों व बिचौलियों के चक्कर में न केवल कई गुणा अधिक रिश्वत देने को मजबूर हैं बल्कि अपना बेशकीमती समय भी इनके चक्करों में बर्बाद कर रहे हैं। लोग अपने दस्तावेज़ लेकर बाबू के सामने रखते हैं तो बाबू कहता है कि वह तो केवल ऑनलाइन कम्प्यूटर पर आये दस्तावेज़ ही देख सकता है, सामने मेज पर रखे दस्तावेज वह नहीं देख सकता। यदि कोई चतुर, बाबू के सामने ही बैठ कर अपने लैपटॉप से बाबू को ऑनलाइन दस्तावेज भेजता है तो बाबू कहता है कि सर्वर डाउन है, साइट काम नहीं कर रही है, जब साइट चलेगी तो वह दस्तावेज़ देखेगा। बस यही खेल हफ्तों और महीनों चलता रहता है।

इस तरह का कोई इक्का-दुक्का तो मामला है नहीं। 'हूडा', एमसीएफ़ तथा तहसील से लेकर हरियाणा सरकार के हर कार्यालय में यह तमाशा लगातार बीते करीब एक साल से चला आ रहा है और मीडिया में इसकी लगातार रिपोर्टिंग होने के बावजूद खट्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में ये क्यों न समझा जाये कि 'भ्रष्टाचार रोकने का जुनून' बताने वाले खट्टर का असली उद्देश्य भ्रष्टाचार को अधिक से अधिक बढ़ा कर जनता की ऐसी-तैसी करना है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि दफ्तरों के चक्कर काटे बगैर घर बैठे लोगों के काम ऑनलाइन हो जायें तो इससे बढिया कोई बात हो नहीं सकती। परन्तु इसके लिये सरकार व उसके अफ़सरों की नीयत का साफ़ होना जरूरी है। जो सरकारी मशीनरी रिश्वतखोरी के बगैर चल नहीं सकती वह भला ऑनलाइन व्यवस्था को क्यों चलने देगी? रही-सही कसर राजनेता मोटे चंदे लेकर निकम्मे ठेकेदारों को ठेका देकर पूरी कर देते हैं।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421